सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सप्लाई की जाने वाली प्रस्तावित वस्तुएं

3814. **श्री अनंतराम जायसवाल :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से किन-किन वस्तुओं की सप्लाई किए जाने का प्रस्ताव है ;

(ख) आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान इन दुकानों के माध्यम से कौन-कौन सी वस्तुएं बेचे जाने का प्रस्ताव है ;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सप्लाई की जाने वाली वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रण में रखने हेतु उनके लिए राज सहायता देने का विचार रखती है ; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक वस्तु के लिए कितनी राजसहायता दी गई है ?

नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार प्रमुख आवश्यक वस्तुओं, जैसे चावल, गेंहू, लेवी चीनी, आयातित खाद्य तेलों, मिट्टी के तेल तथा साफ्ट कोक की अधिप्राप्ति, भंडारण तथा ढुलाई के लिए जिम्मेदार हैं और उपभोक्ताओं में वितरण के लिए राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को इनका थोक में आवंटन करती हैं। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में स्थानीय आबादी की पसंद को ध्यान में रखते हुए आम खपत की अतिरिक्त वस्तुओं की अधिप्राप्ति करें तथा उन्हें इस प्रणाली में शामिल करें। कुछ राज्य सरकारें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बिक्री केन्द्रों से दालें, साबुन, आयोडीनयुक्त नमक, मसाले, चाय, दियासलाई जैसी आम खपत की अतिरिक्त वस्तुओं का वितरण कर रही हैं।

नवीनीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली में, जिसके तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से 1700 ब्लाकों को चुना गया है, राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे दालों (चना), चाय, आयोडीनयुक्त नमक तथा साबुन जैसी वस्तुओं का उपभोक्ताओं में वितरण करने का कार्य आरंभ करें। केन्द्रीय सरकार प्रमुख आवश्यक वस्तुओं, जिनके लिए उसने जिम्मेदारी ले रखी है, की अधिप्राप्ति भंडारण तथा ढुलाई पर पहले ही समग्रतः राजसहायता वहन करती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरित की जाने वाली अतिरिक्त वस्तुओं पर राजसहायता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Pink And Green Ration Cards

3815. SHRI SURESH KALMADI : Will the PRIME MINISTER be pleased to state.

(a) whether it is a fact that Government propose to issue ration cards in two colours pink and green in place of the one coloured cards issued since the beginning of the rationing system; and

(b) if so, the reasons therefor; and what additional benefits it will accrue to holders?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) and (b) Issue of ration cards is done by the State Governments/UT Administrations to people living in their jurisdiction to enable them to obtain supply of PDS items. Some State Governments, however, have introduced a dual card system based on incomes. The Central Government has no proposal at present to issue any guidelines to the States/UTs for issuing ration cards in two colours.